आंकड़ों में बढ़त

हाल ही में नीति आयोग ने 'स्कूल एज्यूकेशन क्वालिटी इंडेक्स' जारी किया है। इस इंडेक्स में शिक्षा की गुणवत्ता के हिसाब से केरल पहले पर व राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स का आधार जो 30 सूचक या इंडिकेटर बने हैं उन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन दो श्रेणियों के भीतर फिर और श्रेणियां हैं :

- श्रेणी 1 : प्रतिफल या आउटकम आधारित
  - क्षेत्र/डोमेन 1 : लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल
  - क्षेत्र/डोमेन 2 : पहुंच आधारित प्रतिफल
  - क्षेत्र/डोमेन 3 : आधारभूत संरचना व सुविधाओं पर आधारित प्रतिफल
  - क्षेत्र/डोमेन 4 : इक्विटी या समता आधारित प्रतिफल (इन चारों डोमन में कुल 16 मानक हैं)
- श्रेणी 2 : सरकारी प्रक्रियाओं से प्राप्त मदद पर आधारित
  - इसमें कितने छात्रों शिक्षा में शामिल हो पाए, शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, प्रशिक्षण, स्कूल नेतृत्व, प्रर्याप्त प्रशासनिक ढांचा, जवाबदेही, पारदर्शिता आदि जैसे 14 मानक शामिल हैं।

इस इंडेक्स की शुरुआत सन् 2015-16 में की गई थी। उसके बाद इसे जारी करने का यह दूसरा (2016-17 के लिए) मौका है।

इस इंडेक्स में राजस्थान दूसरे स्थान पर आया है लेकिन उसकी आधारभूत संरचना व सुविधाओं पर आधारित प्रतिफल के मामले में स्थिति बेहद खराब है। उसके दूसरे स्थान पर आने की वजह लर्निंग आउटकम्स या सीखने के प्रतिफल बने हैं। यहां राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन आंकड़ों में राजस्थान बेहतर प्रदर्शन करने वाले अव्वल राज्यों में शामिल रहा है। दूसरी ओर 'असर 2018-19' रिपोर्ट है जिसके आंकड़ों में राजस्थान उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पांच राज्यों में शामिल रहा है। हम जानते हैं कि असर रिपोर्ट बहुत व्यापक दक्षताओं व क्षमताओं का आकलन करने के लिए नहीं जानी जाती जबकि उसके सापेक्ष राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) ज्यादा व्यापक दायरे में आकलन करता है। उसके बावजूद राजस्थान असर की रिपोर्ट में निचले पांच राज्यों में शामिल होता है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के आंकड़ों में अव्वल राज्यों में। आंकड़ों के इस खेल में क्या झोल है यह समझ से परे है।

इस इंडेक्स में सरकारी प्रक्रियाओं से प्राप्त मदद आधारित प्रतिफल के मामले में ज्यादातर राज्यों का प्रदर्शन खराब रहा है। इसका आशय है कि राज्य व केन्द्र सरकारों को शिक्षा में जितना निवेश करना चाहिए उतना निवेश नहीं कर रही हैं। हरियाणा ने आधारभूत संरचना व सुविधाओं पर आधारित प्रतिफल के मामले में जबरदस्त बढ़त दर्ज करवाई है। यानी स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं के मामले में हरियाणा ने अच्छा काम किया है किन्तु सीखने के प्रतिफल के मामले में वह पीछे रहा है। यानी हरियाणा जैसे राज्यों में स्कूलों के लिए ढांचागत सुविधाएं तो हैं लेकिन शिक्षण के मामलों में वह पीछे है। ऐसे स्कूलों का फायदा क्या है?

असर की रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक 4 में से 1 छात्र पढ़ने की मूलभूत दक्षताएं हासिल किए बिना 8वीं कक्षा पार कर जा रहा है और असर के हिसाब से इसका मतलब है भाषा में शब्द व सरल वाक्य भी नहीं पढ़ पाना। गणित में यह घटाव या बाकी का सवाल हल नहीं कर पाना जैसी है। शिक्षा की इस हालत की ताकीद विभिन्न राज्यों में 9वीं कक्षा के स्तर पर तेजी से शुरू किए जा रहे कम समयावधि के वे ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, जिनमें 9वीं में पहुंच गए बच्चों को पढ़ने-लिखने की मूलभूत दक्षताएं व क्षमताएं सिखाने का काम किया जा रहा है ताकि वे गणित, विज्ञान जैसे दूसरे विषयों को पढ़ पाने में समर्थ बन सकें। कम से कम उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में 9वीं के स्तर पर ऐसे ब्रिज कोर्स चलाए जाने की जानकारी सामने आई है।

असर की रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 से अब तक लगातार 6-14 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन 96प्रतिशत के आसपास रहा है। इन वर्षों के दौरान नामांकन में 'जेंडर गैप' तेजी से कम हुआ है। 11-14 वर्ष आयुवर्ग की लड़कियों में स्कूल से बाहर छूट जाने वाली लड़कियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। वर्ष 2006 से 2018 के दौरान लगभग सभी राज्यों में निजी स्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ा है। नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2016-17 में छात्र-छात्राओं की प्राथमिक स्तर (कक्षा 5) से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6) में जाने की दर 90 प्रतिशत से भी ज्यादा रही है। 'न्यूपा' की रिपोर्ट- 'Elementary Education in India: Trend 2005–06 to 2015–16' बताती है कि 2009-10 से 2015-16 के बीच इसी दौरान निजी स्कूलों की संख्या भी तेजी से बढ़कर 2,54,178 से 3,34,468 हो गई जबकि इसी दौरान सरकारी स्कूलों की संख्या 13,03,812 से बढ़कर 14,49,078 हुई है। हम देख सकते हैं कि सरकारी स्कूलों की संख्या में उस अनुपात में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसी दौर में संविदा शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 2019-10 में जहां संविदा शिक्षकों की संख्या कुल शिक्षकों की 11.0 प्रतिशत थी वहीं 2015-16 में यह संख्या 13.2 प्रतिशत हो गई।

जहां एक ओर यह आंकड़े शिक्षा की जबरदस्त मांग व पहुंच को दर्शाते हैं वहीं भाषा और गणित के आकलनों के परिणाम शिक्षा की लगातार गिरती जा रही गुणवत्ता को दर्शाते हैं। संविदा शिक्षकों की लगातार बढ़ती संख्या, निजी स्कूलों की संख्या में तेजी से होती बढ़ोतरी और शिक्षा के बजट में होती लगातार कटौती यह दर्शाती है कि शिक्षा में सरकारी निवेश लगातार कम होता जा रहा है। हम शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य को हासिल करने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं मगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वजनीनकरण से कोसों दूर हैं। जबकि गुणवत्ता शिक्षा का मूल व आवश्यक घटक है। क्या इसे इस नज़र से भी देखे जाने की जरूरत है कि जिस तेजी से समाज के वंचित तबके की भागीदारी शिक्षा हासिल करने में बढ़ी है उसी तेजी से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है! और क्या इसका हमारे समाज में मौजूद जाती, वर्ग, लिंग आदि आधारित विषमता से कोई गहरा रिश्ता है? क्या इस नज़र से इसकी समाजशास्त्रीय विवेचना किए जाने से कोई अंतर्दृष्टि हमें मिल सकती है!

हम आंकड़ों में चाहे कितनी भी वृद्धि हासिल कर लें, शिक्षा में सवाल यह है कि हम कितने निचले स्तर से शुरू कर रहे हैं और वृद्धि को कितने निचले स्तर पर दर्ज किया गया है? बहुत निचले स्तर पर दर्ज की गई बढ़त आंकड़ों में तो दिखेगी और शायद सफलता का ढोल पीटने के काम भी आए। लेकिन हकीकत में शिक्षा का कितना फायदा करेगी यह एक बड़ा सवाल है? ◆

प्रमोद